आकाशवाणी केन्द्र शिमला

08.01.2026 / संजय / 11.00बजे

प्रादेशिक समाचार

जनगणना

केंद्र सरकार ने जनगणना–2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर, 2026 के बीच घरों की सूची बनाने के साथ ही इसकी गणना की जाएगी। दूसरे चरण के तहत फरवरी, 2027 में जनसंख्या की गणना होगी।

राज्यपाल

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 9 से 12 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संवाद कार्यक्रम में देश भर से तीन हजार युवा प्रतिभागी भाग लेंगे जिनमें हिमाचल प्रदेश से भी 35 युवा शामिल हैं।

वीबी–जी राम जी

ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित भारत सरकार की विकसित भारत–जी राम जी योजना आकांक्षी जिला चंबा के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। इस योजना का स्वागत करते हुए ग्रामीण परिवेश से संबंधित जिलावासियों के अनुसार भारत सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना से आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों की तस्वीर ही बदल जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

करूणामूलक

प्रदेश सरकार ने करुणामूलक नियुक्ति से जुड़ी नीति में कुछ बदलाव किए हैं। वित्त विभाग ने इस बारे में कार्यालय आदेश जारी किया है। इसके तहत अब करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का अधिकार संबंधित विभाग के पास ही रहेगा। लेकिन जूनियर ऑफिस सहायक (आईटी) के पद के लिए

एक अलग मापदंड तय किए गए हैं। इसमें संबंधित विभाग पहले सभी जरूरी कागजात और योग्यता की जांच करेगा। इसके बाद उम्मीदवार का मामला कार्मिक विभाग के भर्ती निदेशालय को भेजा जाएगा। भर्ती निदेशालय की मंजूरी मिलने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

स्टार्ट अप योजना

बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के साथ–साथ प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना बेरोजगारों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। हमीरपुर जिला के भूंपल गांव के रमेश कुमार और मझियार गांव के नसीरदीन भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की शुरुआत की तो रमेश और नसीरद्दीन को तो जैसे बहुत बड़ा सहारा मिल गया। प्रदेश सरकार ने भारी.भरकम सब्सिडी ही नहीं दीए बल्कि इसी योजना के तहत ई.टैक्सी के लिए स्थायी रूप से काम देने का भी प्रावधान कर दिया। रमेश कुमार की इलेक्ट्रिक गाड़ी को जलशक्ति विभाग के भोरंज मंडल में और नसीरद्दीन की गाड़ी को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के साथ अटैच कर दिया गया। यानि इन दोनों वाहन मालिकों एवं चालकों की कारोबार की चिंता भी सरकार ने ही दूर कर दी। इस सराहनीय योजना की बार–बार प्रशंसा और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए रमेश कुमार तथा नसीरद्दीन का कहना है कि इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से डबल फायदा हुआ है। हिमाचल को प्रदूषण मुक्त एवं हरित राज्य बनाने की दिशा में भी यह योजना एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है।

एचपीएमसी

एच पी एम सी ने एम आई एस के तहत पिछले साल खरीदे गए सेब के नकद भुगतान से जुड़े अपने आदेशों में संशोधन किया है। संशोधित आदेशों के तहत अब छोटे बागवानों से राजस्व रिकॉर्ड लेना अनिवार्य नहीं होगा और केवल उन्हीं सेब बागवानों से राजस्व रिकॉर्ड लिया जाएगा जिनकी एक सौ से अधिक सेब की बोरियां होंगी। इस संबंध में एच पी एम सी के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किए हैं।